



318hi29

29

सरकार का बजट

सामान्यतः भारत में प्रत्येक वर्ष फरवरी मास में संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। जब वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट संसद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता है। बजट प्रस्तुत किए जाने से काफी दिन पहले लोग अनुमानित विभिन्न करों में परिवर्तनों को लेकर अटकलें लगाते हैं। क्या आयकर की दर को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा? क्या पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें अपरिवर्तनीय रहेंगी? हम सब बजट के आपेक्षित कर परिवर्तनों की चर्चा करते हैं, क्योंकि इनसे वस्तुओं और सेवाओं पर भविष्य में होने वाले व्यय पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे यह गलत धारणा पैदा हो सकती है कि सरकार का बजट केवल विभिन्न करों से ही संबंधित कार्य होता है, परंतु वास्तव में, सरकार का बजट करों के परिवर्तन के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है।

यह पाठ सरकार के बजट की संरचना एवं उद्देश्यों का वर्णन करता है। इस पाठ में आप सरकार के बजट का अध्ययन करेंगे और जान पाएंगे कि यह मात्र करों की दरों में परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ और भी है।



उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप:

- सरकारी बजट का अर्थ समझ पाएंगे;
- सरकार के बजट की संरचना को समझ पाएंगे;
- राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर कर पाएंगे;
- राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में अंतर कर पाएंगे;
- योजना एवं गैर योजना व्यय में अंतर कर पाएंगे;
- राजकोषीय घाटा, बजट घाटा तथा प्राथमिक घाटे का अर्थ समझ पाएंगे;
- विभिन्न घाटों को पूरा करने के वित्तीय उपायों को समझ पाएंगे; तथा
- बजटीय नीति का अर्थ व उद्देश्यों को समझ पाएंगे।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ



टिप्पणियाँ

29.1 सरकार का बजट क्या होता है?

सरकार का बजट सरकार का एक वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का मद वार ब्यौरा है। भारत में वित्तीय वर्ष दो कलेंडर वर्ष में पहली अप्रैल से 31 मार्च की अवधि होती है।

सरकार प्रत्येक स्तर पर चाहे केन्द्रीय स्तर हो अथवा राज्य या स्थानीय स्तर, प्रत्येक स्तर पर बजट तैयार करती है। इसे लोक कल्याण के लिए सरकार की सामान्य नीतियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।

सरकार विभिन्न सुविधाएं, जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने हेतु विभिन्न व्यय करती है। वह उत्पादन बढ़ाने, बेरोजगारी, गरीबी तथा आय और संपत्ति की विषमताओं को कम करने में धन व्यय करती है। इस प्रकार का व्यय सरकार की लोक कल्याण नीति को प्रोत्साहित करता है। इन व्ययों के लिए सरकार कर, सार्वजनिक ऋण आदि स्रोतों से राजस्व जुटाती है। इन वित्तीय संसाधनों को, जो सरकारी व्यय के लिए कोष प्रदान करते हैं, जनता से जुटाया जाता है।

व्यय की मदें तथा उनके वित्त के लिए संसाधनों की, लोक कल्याण के उद्देश्य के अनुसार सरकार द्वारा योजना बनाई जाती है। अतः व्यय के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत सार्वजनिक धन को किस प्रकार व्यय किया जाए तथा विभिन्न स्रोतों से इसे कैसे जुटाया जाए, के संबंध में जनता की ओर से निर्णय लेती है। यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। संसद, विधानमंडल एवं दूसरे विभिन्न निकायों द्वारा जनता अपने अधिकार का प्रयोग यह जानने के लिए करती है कि सरकार जनता के धन को किस प्रकार व्यय कर रही है और उसे उनसे किस प्रकार वसूल कर रही है। देश की जनता के प्रति सरकार के इस उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति सरकार के बजट में होती है। बजट एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित लोकव्यय एवं लोक राजस्व पर आधारित सरकार द्वारा तैयार किया गया एक समेकित वित्तीय विवरण है।

सरकार के बजट की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक, यह सरकार के अनुमानित व्यय एवं राजस्व के स्रोतों का समेकित वित्तीय विवरण है। दो, यह एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है तथा तीन, व्यय एवं सरकार के राजस्व के स्रोतों की सरकार द्वारा घोषित नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार योजना बनाई जाती है।

29.2 बजट की संरचना

सरकार के बजट के मूल ढांचे और उसके विभिन्न घटकों को समझने के लिए आइए, हम सारणी 29.1 में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भारत की केन्द्र सरकार के बजट पर विचार करें। इस सारणी से हमें पता चलता है कि बजट के दो भाग हैं :

1. प्राप्तियां और 2. व्यय

तालिका 29.1: केन्द्रीय बजट: केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियां और व्यय
(रु. करोड़ में)

	2012-2013
	Actuals
1. राजस्व प्राप्तियां	877613
2. कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	740256
3. कर भिन्न राजस्व	137357
4. पूंजी प्राप्तियां (5+6+7)	532754
5. ऋणों की वसूली	16267
6. अन्य प्राप्तियां	25890
7. उधार और अन्य देयताएं	490597
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	1410367
9. आयोजना-भिन्न व्यय	996742
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	914301
11. ब्याज भुगतान	313169
12. पूंजी खाते पर	82441
13. आयोजना व्यय	413625
14. राजस्व खाते पर	329208
15. पूंजी खाते पर	84417
16. कुल व्यय (9+13)	1410367
17. राजस्व व्यय (10+14)	1243509
18. जिसमें पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	115513
19. पूंजी व्यय (12+15)	166858
20. राजस्व घाटा (17-1)	365896
	(3.6)
21. प्रभावी राजस्व घाटा	250383
Deficit(20-18)	(2.5)
22. राजकोषीय घाटा	490597
(16-(1+5+6))	(4.9)
23. प्राथमिक घाटा (22-11)	177428
	(1.8)



टिप्पणियाँ

1. प्राप्तियां

सरकार की प्राप्तियां विभिन्न स्रोतों को दर्शाती हैं, जिनसे सरकार राजस्व वसूलती है। ये प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं—1. राजस्व प्राप्तियां, 2. पूंजीगत प्राप्तियां।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

सरकार का बजट

राजस्व प्राप्तियाँ सभी स्रोतों से प्राप्त वर्तमान आय होती है, जैसे—कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान आदि। राजस्व प्राप्तियाँ सरकार पर न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती हैं और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। दूसरी तरफ पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ होती हैं, जिनसे या तो देनदारी उत्पन्न होती है अथवा सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। उदाहरणार्थ : ऋण, ऋणों की वसूली तथा विनिमेश आदि।

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति द्वारा वित्त पोषण एवं सरकार द्वारा वित्त पोषण में समानता होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने चालू व्यय की वित्त पूर्ति अपनी चालू आय से करता है। जब उसकी चालू आय उसके चालू व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती तो उसे ऋण लेना पड़ता है। इसी प्रकार सरकार के पास अपने व्यय की वित्त पूर्ति के दो स्रोत हैं—चालू आय या राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। जब राजस्व प्राप्तियाँ चालू व्यय से कम पड़ती हैं, तब सरकार ऋण लेती है। एक व्यक्ति द्वारा वित्तीयन एवं सरकार द्वारा वित्तीयन के मध्य अंतर यह है कि एक व्यक्ति पहले अपनी चालू आय का अनुमान लगाता है और फिर अपने व्यय को योजना का रूप देता है, जबकि सरकार अपने व्यय की योजना पहले बनाती है और फिर अपने वित्तीयन के स्रोतों का पता लगाती है।

1. राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की चालू आय होती है, जिनसे न तो देनदारी उत्पन्न होती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इन प्राप्तियों को (क) कर राजस्व एवं (ख) गैर कर राजस्व में वर्गीकृत किया जाता है।

(क) कर राजस्व

कर जनता और फर्मों द्वारा देश की सरकार को बदले में बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के किए जाने वाला एक वैधानिक तथा अनिवार्य भुगतान होता है। सरकार जनता पर कर लगाती है। सरकार विभिन्न करों, जैसे—आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पादन कर, आयात कर आदि के द्वारा राजस्व वसूलती है। परंपरागत रूप से करों द्वारा प्राप्त राजस्व सरकार की आय का सर्वप्रमुख स्रोत है।

आय कर उन लोगों पर लगाया जाता है, जो आय आय अर्जित करते हैं जैसे, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज तथा लाभ। बिक्री कर वह कर होता है जो वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। जब भी हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं, हमारे भुगतान का एक भाग बिक्री कर के रूप में सरकार के पास जाता है। सेवा कर वह कर है, जब हम सेवा का उपयोग करते हैं तो भुगतान करते हैं, जैसे—दूरभाष सेवा। उत्पादन कर वस्तुओं के उत्पादन करने में निर्माता के द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर है। आयात निर्यात कर का भुगतान तब किया जाता है, जब हम किसी वस्तु का आयात अथवा निर्यात करते हैं।

सभी कर दो प्रकार के होते हैं—

- (क) प्रत्यक्ष कर और
- (ख) अप्रत्यक्ष कर।



टिप्पणियाँ

इनके बीच का अंतर निर्भर करता है—1. सरकार को भुगतान करने के दायित्व और 2. कर के वास्तविक भार पर।

प्रत्यक्ष कर के भुगतान का दायित्व एवं कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, आय कर एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि व्यक्ति जिस पर अदायगी का दायित्व है, वही कर भार वहन भी करता है। यह भार दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष कर के संबंध में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए बिक्री कर के संदर्भ में यद्यपि कर का दायित्व वस्तुओं के विक्रेता पर होता है, पर कर का वास्तविक भार ग्राहक पर ही पड़ता है। अंत में विक्रेता को नहीं, बल्कि क्रेता को ही बिक्री कर का भुगतान करना पड़ता है। विक्रेता केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि करके ग्राहकों से कर लेकर सरकार को भुगतान कर देता है। अतः बिक्री कर के बाद में हम पाते हैं कि कर का भार विक्रेता से खिसककर ग्राहक पर चला जाता है। उत्पादन पर लगने वाले सभी कर अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उत्पादक वस्तु की कीमत में वृद्धि करके इन करों को ग्राहकों से वसूल करते हैं।

प्रत्यक्ष कर के उदाहरण

- आय कर : व्यक्तियों की आय पर कर
- निगम कर : निगमों के लाभ पर कर
- संपत्ति कर : व्यक्तियों की संपत्ति पर कर
- उपहार कर : दिए जाने वाले उपहार पर कर

अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण

- मूल्य वृद्धि कर
- उत्पादन कर : कारखानों में उत्पादित वस्तुओं पर कर
- आयात-निर्यात कर : आयात तथा निर्यातों पर कर
- सेवा कर : उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर कर

प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर

क्र.सं.	आधार	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1.	कराघात	प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों या फर्मों पर लगाया जाता है।	अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं।
2.	भार का स्थानांतरण	प्रत्यक्ष कर का भार दूसरे पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता अर्थात् कराघात तथा कर का भार एक ही व्यक्ति पर होगा।	कर का भार दूसरे पर खिसकाया जा सकता है अर्थात् कराघात तथा कर का भार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर होते हैं। उदाहरण के लिए विक्रेता वस्तु की कीमत में वृद्धि कर सकता है ताकि क्रेता कर के भार को वहन करे।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

सरकार का बजट

3.	प्रकृति	ये कर सामान्यतः प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं।	इनकी प्रकृति आनुपातिक होती है।
4.	क्षेत्र	इनका क्षेत्र सीमित होता है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक इनकी पहुंच नहीं होती।	इन करों का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं।

(ख) गैर कर राजस्व

कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त होने वाली आये गैर कर राजस्व होती है। भारत में केन्द्रीय सरकार के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

1. व्यापारिक राजस्व

यह सरकार को जनता को प्रदत्त वस्तुओं व सेवाओं की कीमत के रूप में प्राप्त होती है, जैसे लोगों द्वारा विद्युत, रेल डाक टिकट, चुंगी आदि की सेवाओं के लिए भुगतान।

2. प्रशासनिक राजस्व

यह सरकार की प्रशासनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। ये निम्नलिखित हैं:

- (क) पासपोर्ट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, शिक्षा शुल्क, कोर्ट फीस, सरकारी अस्पताल की फीस आदि के रूप में फीस।
- (ख) जुर्माना और दंड : सरकार द्वारा कानून तोड़ने वालों से नियमों तथा अधिनियमों का पालन नहीं करने के लिए वसूल किए जाने वाला जुर्माना।
- (ग) लाइसेंस तथा परमिट फीस।
- (घ) राजगमन वह आय जो सरकार को उस संपत्ति पर अधिकार लेने से मिलती है, जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।
- (ङ) ब्याज प्राप्तियां।
- (च) सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ।

3. पूंजीगत प्राप्तियां

जैसा पहले बताया गया है कि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं, जिनमें सरकार की या तो देनदारी बढ़ती है या यह उसकी संपत्तियों को कम करती हैं। केन्द्रीय सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं—

1. ऋण : जिनसे सरकार ऋण लेती है, उनके दो स्रोत हैं :

- (क) घरेलू ऋण : सरकार प्रतिभूतियों एवं कोष पत्रों को जारी कर घरेलू वित्तीय बाजार से ऋण लेती है। यह विभिन्न जमा योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, लघु बचत, योजनाओं, सार्वजनिक ऋण एवं राष्ट्रीय बचत पत्रों आदि के माध्यम से जनता से भी ऋण लेती है। यही देश के अंदर सरकार का ऋण कहलाता है।

(ख) बाह्य ऋण : घरेलू ऋण के अतिरिक्त सरकार विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे—अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि से भी ऋण लेती है। सरकार विदेशी ऋणों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय लाती है।

2. ऋणों की वसूली

प्रायः राज्य व स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से कर्ज लेती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य व स्थानीय सरकारों से ऋणों की वसूली को बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ऋणों की वसूली से देनदारों (संपत्तियों) में कमी आती है।

3. विनिवेश

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री—यह पूंजीगत प्राप्तियों का एक नवीनतम स्रोत है, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार 1991 से वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर रही है। 1991 से पूर्व केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंशों की शत-प्रतिशत स्वामी थी। 1991 से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की नीति अपनाई। फलतः इसने आम जनता एवं वित्तीय संस्थाओं को शेयर बेचना आरंभ कर दिया। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की इस बिक्री को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कहते हैं।

2. व्यय

सरकारी व्यय को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :

1. पूंजीगत व्यय व राजस्व व्यय तथा
2. योजना व्यय व गैर योजना व्यय

पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय

जब सरकार परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे—विद्यालय तथा चिकित्सालय के भवन, सड़कें, पुल, नहर, रेल पटरी इत्यादि परिसंपत्तियों के निर्माण पर अथवा देयताओं को कम करने जैसे ऋण आदि के भुगतान पर व्यय करती है तो ऐसा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। परंतु जब सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न किसी देयता में कमी आती है जैसे—सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, सरकारी संपत्ति का रख-रखाव, लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा उपलब्ध कराना इत्यादि राजस्व व्यय कहलाते हैं। इनसे किसी लोक संपत्ति का निर्माण नहीं होता है।

योजना व्यय और गैर योजना व्यय

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नियोजन के मार्ग को अपनाया। नियोजन के अंतर्गत सरकार के बजट में पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार का व्यय योजना व्यय कहलाता है।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

सरकार का बजट

योजना व्यय के अतिरिक्त सरकार रोजमर्रा की चीजें, जैसे—पुलिस, न्यायिक प्रणाली, जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, विधायिका, रक्षा एवं सरकार के विभिन्न विभागों पर भी व्यय करती है। इस प्रकार की रोजमर्रा के व्ययों को गैर योजना व्यय कहते हैं।



पाठगत प्रश्न 29.1

सही विकल्प को चुनिए:

- सरकार का बजट किसका वित्तीय विवरण है—
 - वास्तविक व्यय एवं वास्तविक प्राप्तियों का
 - अनुमानित व्यय एवं अनुमानित प्राप्तियों का
 - अनुमाति व्ययों का
 - अनुमानित प्राप्तियों का
- निम्न में से कौन पूंजीगत प्राप्तियां हैं—
 - कर
 - लाभांश
 - लाभ
 - ऋण, ऋणों की वसूली, विदेशों से प्राप्त अनुदान।
- राजस्व प्राप्तियां कौन-सी हैं—
 - ऋण
 - ऋण वसूली
 - विदेशों से प्राप्त अनुदान
 - कर, ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने वाला लाभांश व लाभ
- सरकार का रक्षा पर किया गया व्यय है—
 - राजस्व व्यय
 - पूंजीगत व्यय
 - योजना व्यय
 - गैर-योजना व्यय

29.3 संतुलित बजट बनाम घाटे का बजट या बचत का बजट

जैसा कि पहले समझाया जा चुका है—सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय बजट के दो घटक हैं। प्राप्तियों तथा व्यय के संदर्भ में बजट तीन प्रकार का हो सकता है—1. संतुलित बजट, 2. घाटे का बजट और 3. बचत का बजट।

- जब सरकार का व्यय ठीक उसकी प्राप्तियों के बराबर होता है तो उसे सरकार का संतुलित बजट कहा जाता है।
- जब सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह घाटे का बजट होता है।
- जब सरकार की आय व्यय से अधिक होती है, तब बचत का बजट होता है।

अतः

संतुलित बजट = कुल बजटीय प्राप्तियां = कुल बजटीय व्यय

घाटे का बजट = कुल बजटीय प्राप्तियां > कुल बजटीय व्यय

बचत का बजट = कुल बजटीय प्राप्तियां < कुल बजटीय व्यय

एक समय था, जब बजट की बचत को अच्छे बजट का सूचक माना जाता था, किंतु आधुनिक अर्थव्यवस्था में घाटे के बजट का प्रचलन है।

29.4 बजट घाटे के प्रकार

बजट घाटे की तीन अवधारणाएं हैं—

(क) राजस्व घाटा

इससे अभिप्राय सरकार के कुल राजस्व व्यय पर उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों के आधिक्य से है अथवा राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - (कर राजस्व + गैर-कर राजस्व)

राजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियां

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटे को एक वित्त वर्ष में ऋणों को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।

राजकोषीय घाटा = कुल बजटीय व्यय - ऋणों को छोड़कर कुल बजटीय प्राप्तियां

अथवा राजकोषीय घाटा = (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) - (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां)

राजकोषीय घाटा बजट वर्ष में सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटा ब्याज के भुगतान सहित व्यय के वित्तीयन के लिए सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

सरकार का बजट

राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय – राजस्व प्राप्तियां – ऋणों को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां

अथवा राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय – कर राजस्व – गैर कर राजस्व – ऋणों की वसूली – विनिमेश

अथवा राजकोषीय घाटा = सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता

राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की अतिरिक्त राशि को सूचित करता है। दो, यह सरकार की ब्याज का भुगतान तथा ऋण के भुगतान पर भावी देयताओं में वृद्धि का सूचक है। सरकार के लिए गए ऋण की राशि को ब्याज के साथ भविष्य में चुकाना पड़ता है। फलस्वरूप, सरकार को ब्याज और ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए या तो लोगों से अधिक ऋण लेना पड़ता है या लोगों पर भविष्य में अधिक कर लगाने पड़ते हैं।

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा घटा पिछले ऋणों पर ब्याज का भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान को छोड़कर व्यय को पूरा करने के लिए सरकार की ऋण की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। अतः प्राथमिक सकल प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान।

निवल प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा + प्राप्त ब्याज – ब्याज भुगतान।

यह केंद्र सरकार की कुल उस राशि को दर्शाता है, जो उसे उधार लेनी है।

घाटे के वित्त पोषण के तरीके

सरकार तीन तरह से घाटे का वित्त पोषण करती है—

(क) जनता एवं विदेशी सरकारों से ऋण

(ख) भारतीय केन्द्रीय बैंक (RBI) से नकद शेष की निकासी

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण।

सामान्यतः सरकार रिजर्व बैंक से नकद शेष की निकासी या इससे ऋण लेने की बजाय अपने नागरिकों या विदेशी सरकारों से ऋण लेना पसंद करती है। घाटे के वित्त पोषण के अंतिम दो तरीके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि होती है। दूसरी ओर, नागरिकों से ली गई घरेलू ऋण, मुद्रा की पूर्ति एवं कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि जब सरकार ऋण लेती है तो जनता का पैसा सरकार के हस्तांतरित हो जाता है एवं मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सरकार का विदेशों से ऋण लेने में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। घाटे के वित्त पोषण के अंतिम दो तरीके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाते हैं। कोई भी पैसा जो RBI से बाहर आता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता है और घरेलू अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि करता है।

29.5 बजटीय (राजकोषीय) नीति

अब आप बजटीय नीति के संबंध में जानेंगे। यह नीति दो मुद्दों से संबंधित हैं, जो नीचे दिए गए हैं—

1. वे मदें, जिन पर सरकार को व्यय करना चाहिए
2. अपने वित्तीयन के लिए सरकार को संसाधन किस प्रकार जुटाने चाहिए।

पहले प्रश्न का उत्तर देश के सम्मुख विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ अगर दूसरे देशों से आक्रमण की निरंतर आशंका बनी रहती है तो सरकार के पास रक्षा पर व्यय बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगर किसी महामारी के फैलने की आशंका हो तो सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक व्यय करना पड़ता है। अगर सरकार ने भूतकाल में ऋण लिया हुआ है तो उसे ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करना पड़ेगा।

दूसरे प्रश्न में सरकार को संसाधन जुटाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करना पड़ता है। क्या जनता पर और अधिक कर लगाया जाए? किस वर्ग के लोगों पर अधिक कर लगाया जाए? किन वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाया जाए? सरकार को कितना ऋण लेना चाहिए? किससे ऋण लिया जाए और किस रूप में? इन प्रश्नों का उत्तर सरकार के नीति उद्देश्यों में मिलता है।

राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व को बढ़ाने तथा व्यय में वृद्धि करने से संबंधित है। राजस्व का सृजन करने तथा व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार की वित्तीय नीति को बजटीय नीति अथवा राजकोषीय नीति कहते हैं।

प्रमुख राजकोषीय उपाय निम्नलिखित हैं:

1. **सार्वजनिक व्यय** : सरकार अनेक प्रकार की वस्तुओं पर धन खर्च करती है, सेना और पुलिस से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं तथा हस्तांतरण भुगतान जैसी कल्याण सेवाओं पर भी।
2. **कराधान** : सरकार नए कर लगाती है तथा वर्तमान करों की दरों में परिवर्तन करती है। सरकार के व्यय की पूर्ति कर लगाकर की जाती है।
3. **सार्वजनिक ऋण** : सरकार बांड, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र आदि के माध्यम से जनता से तथा विदेशों से भी धन जुटाती है।
4. **अन्य उपाय** : सरकार द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय हैं :
 - (अ) राशनिंग और कीमत नियंत्रण
 - (ब) मजदूरी नियंत्रण
 - (स) वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना





टिप्पणियाँ

बजटीय नीति के उद्देश्य

(क) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करना

सरकार आधारभूत एवं भारी उद्योगों, जैसे—इस्पात उद्योग, रसायन, उर्वरक, मशीन आदि की स्थापना कर आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन करती है। यह आधारीक संरचनाओं, जैसे—सड़कें, नहर, रेल, हवाई अड्डा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जल एवं विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार इत्यादि का भी निर्माण करती है, जो आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हैं।

आधारभूत एवं भारी उद्योग तथा आधारीक संरचनाएं दोनों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः निजी क्षेत्र आगे नहीं आता है। चूंकि ये उद्योग एवं आधारीक संरचना सुविधाएं देश में आर्थिक संवृद्धि के लिए अनिवार्य हैं, इसीलिए इनकी स्थापना और इनको विकसित करने का सारा भार सरकार पर ही पड़ता है।

(ख) आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना

सरकार अमीरों पर कर लगाकर एवं गरीबों पर अधिक व्यय कर आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करती है। साथ ही यह गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे उनको आय कमाने में सहायता करती है।

(ग) रोजगार के अवसर प्रदान करना

सरकार विभिन्न तरीकों से रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। एक, जब वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करती है तो नौकरियों का सृजन करती है। दो, वह निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता एवं दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन, जैसे—करों में छूट, करों की दर को कम करना आदि द्वारा उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह रोजगार को बढ़ावा देने वाले लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ऐसा वह कर में छूट, आर्थिक सहायता, अनुदान, कम ब्याज दर पर ऋण आदि प्रदान करके करती है। अंततः यह सड़कों, पुलों, नहरों, भवनों आदि लोकनिर्माण कार्यक्रमों द्वारा गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करती है।

(घ) मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करना

आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर नियंत्रण कर इनकी कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, सरकार का प्राथमिक कार्य है। इसीलिए सरकार राशन एवं उचित मूल्य की दुकानों पर व्यय करती है। जिनके पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार होता है। यह घरेलू गैस, बिजली, जल एवं आवश्यक सेवाओं जैसे कि यातायात को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और कीमतों को बढ़ने से रोकती है, ताकि आम आदमी उनका उपभोग कर सकें।

(ङ) भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करना

किस देश का भुगतान संतुलन खाता दूसरे देशों के साथ उनकी प्राप्तियां एवं भुगतान को अंकित करता है। जब विदेशियों को किया गया भुगतान विदेशियों से प्राप्तियों से अधिक हो तो भुगतान

संतुलन घाटे में कहा जाता है। प्रायः यह घाटा देश के आयात का निर्यात से अधिक होने पर होता है। फलतः आयात पर विदेशियों को भुगतान निर्यात पर विदेशियों से प्राप्तियों से अधिक होती है। इस स्थिति में भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए सरकार आयात पर कर बढ़ाकर आयात को हतोत्साहित करती है एवं निर्यात पर आर्थिक सहायता एवं दूसरे प्रोत्साहन का उपयोग कर उसे प्रोत्साहित करती है। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आयात पर कर अब लोकप्रिय उपाय नहीं है, क्योंकि इसे देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधा माना जाता है।

(च) प्रभावशाली प्रशासन प्रदान करना।

एक प्रभावशाली प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार पुलिस, रक्षा, विधायिका, न्यायपालिका आदि पर सरकार काफी व्यय करती है।



पाठगत प्रश्न 29.2

कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- (क) सरकार का बजट घाटे में होता है, जब कुल बजटीय व्यय कुल बजटीय राजस्व ...
..... होता है। (से कम, से अधिक, के बराबर)
- (ख) राजकोषीय घाटे में सरकार द्वारा लिया गया ऋण है। (शामिल, शामिल नहीं)
- (ग) बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा का मापदंड है। (बेहतर, खराब)
- (घ) मुद्रा की पूर्ति है, जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है। (कम होती, बढ़ती है)



आपने क्या सीखा?

- बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय एवं राजस्व से संबंधित एक समेकित विवरण है।
- सरकारी बजट में प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं—1. राजस्व प्राप्तियां तथा 2. पूंजीगत प्राप्तियां।
- सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने अंशों को बिक्री को 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश' कहते हैं।
- सरकारी व्यय को इनमें वर्गीकृत किया जाता है—1. राजस्व तथा पूंजीगत व्यय तथा 2. योजना तथा गैर-योजना व्यय



मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ

सरकार का बजट

- राजकोषीय घाटा 'ऋण के अलावा कुल बजटीय प्राप्तियों के ऊपर कुल बजटीय व्यय का आधिक्य है', यह सरकार के कुल ऋण की जरूरत को दर्शाता है।
- केन्द्रीय सरकार तीन तरीकों द्वारा घाटे का वित्तीयन करती है :
 - (क) जनता व विदेशी सरकारों से ऋण
 - (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से नकद शेष की निकासी
 - (ग) रिजर्व बैंकों से ऋण
- सरकारी की नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप व्यय के मदों एवं वित्तीयन के स्रोतों के चुनाव को सरकारी बजटीय नीति कहा जाता है।
- बजटीय नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :
 - (क) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन
 - (ख) आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना।
 - (ग) रोजगार के अवसर प्रदान करना
 - (घ) कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना
 - (ङ) भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करना
 - (च) प्रभावशाली प्रशासन प्रदान करना।



पाठांत प्रश्न

1. सरकार का बजट क्या है? 'वित्तीय वर्ष' से आप क्या समझते हैं?
2. सरकार के बजट की संरचना की रूप रेखा को बताइए एवं इसके विभिन्न घटकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
3. राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों में भेद कीजिए।
4. राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए।
5. योजना तथा गैर-योजना व्यय में अंतर बताइए।
6. बचत के बजट एवं घाटे के बजट में भेद कीजिए। ये कैसे आर्थिक क्रियाओं को सीमित रखते हैं?
7. राजकोषीय घाटे एवं बजटीय घाटा का अर्थ बताइए।

8. राजकोषीय घाटे को बजटीय घाटे की तुलना में घाटे का बेहतर मापदंड क्यों माना जाता है?
9. सरकार के बजट में घाटे के वित्तीयन के विभिन्न तरीके क्या हैं? व्याख्या कीजिए।
10. सरकार द्वारा नागरिकों से एवं भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋण के प्रभाव को समझाइए। इनमें से कौन बेहतर है और क्यों?
11. बजटीय नीति के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए।
12. सरकार के बजट की आवश्यकता को समझाइए।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

29.1

1. ख 2. घ 3. घ

29.2

1. से अधिक
2. शामिल नहीं
3. खराब, बेहतर नहीं
4. बढ़ती है।

मॉड्यूल - 11

मुद्रा, बैंकिंग और सरकार
का बजट



टिप्पणियाँ